साइबर ठगाके सात मामले दर्ज

निवेश से लेकर आनलाइन नौकरी तक के नाम पर ५.८२ लाख रुपये की धोखाधड़ी

जबलपुर, (एजेंसी)। जिले में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के सात मामले सामने आए हैं। कहीं निवेश पर अधिक मुनाफा दिलाने का झांसा देकर रकम हड़पी गई, तो कहीं मोबाइल में एप डाउनलोड कराने और ऑनलाइन नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया। इसके अलावा ड्राईफ्रूट की सप्लाई के नाम पर एडवांस रकम लेकर भी धोखाधड़ी की गई। सात मामलों में कुल ५.८२ लाख की धोखाधड़ी की गई हैं पुलिस ने सभी मामलों में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अधारताल थाना क्षेत्र में बेथल मिशन स्कूल के सामने रहने वाले ५१ वर्षीय किशोर केशवानी ने शिकायत दर्ज कराई कि अज्ञात व्यक्ति ने निवेश पर अधिक आय दिलाने का लालच देकर उनके भारतीय स्टेट बैंक के पचपेढ़ी शाखा स्थित खाते से ८९ हजार रुपये हड़प लिए।

इसी तरह संजीवनीनगर निवासी ४० वर्षीय सुधांशु श्रीवास्तव, जो बड़ेरिया ग्रुप में सिविल इंजीनियर हैं, ने शिकायत की कि इंस्टाग्राम चलाते समय उन्हें एक एप का विज्ञापन दिखाई दिया। उन्होंने एप डाउनलोड किया और बाद में एक अन्य लॉन्चर भी इंस्टॉल कर लिया। २० अक्टूबर की शाम उन्हें बैंक खाते से ९५ हजार रुपये कटने का नोटिफिकेशन मिला। अज्ञात व्यक्ति ने एप के माध्यम से उनके खाते से रकम ट्रांसफर कर ली।

विजय नगर थाना क्षेत्र में विकास नगर निवासी ४४ वर्षीय प्रशांत पांडे के साथ ड्राईफ्रूट की सप्लाई के नाम पर ठगी हुई। शिकायत के अनुसार, २२ अक्टूबर को एक व्यक्ति ने फोन कर ड्राईफ्रूट उपलब्ध कराने की बात कही और एडवांस भुगतान मांगा। उसके बताए दीपक पात्रा के खाते में २५ हजार रुपये ट्रांसफर करने के बाद आरोपी ने फोन नंबर ब्लॉक कर दिया।

विजय नगर में ही एकता नगर निवासी १८ वर्षीय छात्रा आंचल पांडे को ऑनलाइन नौकरी का झांसा देकर १ लाख ८७ हजार १८९ रुपये की ठगी की गई। छात्रा के अनुसार, ११ से १३ अक्टूबर के बीच टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से अलग-अलग क्यूआर कोड भेजे गए और १३ बार में रकम जमा कराई गई।

घमापुर थाना क्षेत्र में कांचघर चौक निवासी ५९ वर्षीय नरेश शर्मा के मोबाइल से ४३ हजार रुपये ट्रांसफर होने का मामला सामने आया है। उन्होंने पुलिस को बताया कि २१ अक्टूबर को मोबाइल चार्ज करने के बाद जब उन्होंने फोन दोबारा देखा तो वह हैंग हो रहा था और उसका डाटा डिलीट हो गया था। बाद में फोन पे की हिस्ट्री जांचने पर स्टेट बैंक खाते से १९ हजार और यूनियन बैंक खाते से २४ हजार रुपये कटने की जानकारी मिली।

गढ़ा थाना क्षेत्र में छुई खदान निवासी १८ वर्षीय ऑटो चालक सौरभ कोरी ने शिकायत की कि १५ अक्टूबर को मोबाइल पर आई एक अनजान लिंक पर क्लिक करने के बाद उनका फोन हैंग होने लगा। कुछ देर बाद बैंक खाते से ९८ हजार ८८५ रुपये कटने का मैसेज आया। फोन पे की हिस्ट्री में यह रकम अंजना दास हलदार के खाते में ट्रांसफर होना दिखाई दिया।

वहीं, बरेला थाना क्षेत्र के कटियाघाट निवासी ५७ वर्षीय रोहिणी प्रसाद कुशवाहा ने भी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ ऑनलाइन धोखाधड़ी कर ४१ हजार रुपये हड़पने की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने इन मामलों में भारतीय न्याय संहिता की धारा ३१८(४) के तहत तथा संबंधित मामलों में धारा ३१९(२) के तहत प्रकरण दर्जकर विवेचना शुरूकर दी है।

फ्लैक्स प्रिंटिंग दुकान में आग लगी, लाखों की मशीनें जली

जबलपुर, (एजेंसी)। गोल बाजार स्थित पुराने जामदार अस्पताल के बगल में स्थित बुधवार की दोपहर २.५० बजे आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग की सूचना मिलते ही नगर निगम का दमकल अमला मौके पर पहुंचा। आग बुझाने के लिए चार दमकल गाड़ियों को लगाया गया। दमकल कर्मियों ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह फिलहाल सामने नहीं आई है। घटना के संबंध में नगर निगम दमकल विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गोलबाजार स्थित पकंज विद्यार्थी के फ्लैक्स प्रीटिंग ग्राफिक्स प्रतिष्ठान विद्या श्री ग्राफिक्स में बुधवार की दोपहर अचानक आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल वाहन मौके पर पहुंचे करीब एक घंटे तक आग बुझाने का काम किया गया इस दौरान दुकान में रखी गई मशीने जलकर क्षतिग्रस्त हो गईं प्रारंभिक तौर पर लाखों रुपए के नुकसान होने की संभावना बताई जा रही है। आग लगने का कारण अज्ञात हैं

भोपाल में हर दस में करीब तीन युवा निठल्ले

एनएसओ की लेबर मार्केट स्नैपशाट आफ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स रिपोर्ट में खुलासा

भोपाल, (एजेंसी)। राजधानी भोपाल सहित प्रदेशभर में युवाओं को शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जोडऩे के लिए योजनाएं तो कई हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि बड़ी संख्या में युवा अब भी इन तीनों से बाहर हैं। भोपाल जिले में १५ से २९ वर्ष आयु वर्ग के २९.२ प्रतिशत युवा न पढ़ाई कर रहे हैं, न रोजगार में हैं और न ही कोई प्रशिक्षण ले रहे हैं। यानी हर १०० में करीब २९ युवा निठल्ले वाली स्थिति में हैं। यह अनुपात प्रदेश के औसत २२ प्रतिशत से ७.२ प्रतिशत अंक अधिक है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की सितंबर २०२६ में जारी लेबर मार्केट स्नैपशॉट ऑफ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स रिपोर्ट के ये आंकड़े राजधानी में युवाओं को अवसरों से जोडऩे की चुनौती सामने रखते हैं। प्रदेश के दस सबसे अधिक आबादी वाले जिलों में इस मामले में भोपाल दूसरे स्थान पर है। ग्वालियर में यह अनुपात २९.३ प्रतिशत के साथ सबसे अधिक है, जबकि जबलपुर में सबसे कम १६.५ प्रतिशत युवा शिक्षा, रोजगार और प्रशिक्षण से बाहर हैं। भोपाल और जबलपुर के बीच १२.७ प्रतिशत अंक का अंतर है।

कामकाजी आबादी में भी भोपाल पीछे

भोपाल की तस्वीर केवल युवाओं तक सीमित नहीं है। जिले में १५ वर्ष और उससे अधिक उम्र की आबादी में महज ४८.१ प्रतिशत लोग काम कर रहे हैं, जबकि प्रदेश का औसत ६४.१ प्रतिशत है। इस पैमाने पर भोपाल राज्य के औसत से १६ प्रतिशत अंक पीछे है। जिले की बेरोजगारी दर ३.९ प्रतिशत है, जो रिपोर्ट में शामिल दस बड़े जिलों की उपलब्ध दरों में सबसे अधिक है। ये आंकड़े संकेत देते हैं कि राजधानी में शिक्षा और रोजगार के अवसरों को युवाओं तक पहुंचाने के साथ ही कौशल प्रशिक्षण को वास्तविक रोजगार से जोडऩे की जरूरत है। हालांकि, पढ़ाई, रोजगार और प्रशिक्षण से बाहर युवाओं का अनुपात सीधे बेरोजगारी दर नहीं बताता। इसमें वे युवा भी शामिल हैं, जो फिलहाल इन तीनों गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले रहे हैं।

योजनाओं के बावजूद पहुंच की चुनौती

युवाओं को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए समग्र शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री-एग्जिट व्यवस्था पढ़ाई बीच में छोडऩे वाले विद्यार्थियों को दोबारा शिक्षा शुरू करने का अवसर देती है। मेधावी विद्यार्थी, जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं के जरिये आर्थिक सहायता भी दी जाती है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में युवाओं का शिक्षा और प्रशिक्षण से बाहर रहना योजनाओं के क्रियान्वयन और पहुंच पर सवाल खड़े करता है। शिक्षाविदों के अनुसार, केवल योजना शुरू करना पर्याप्त नहीं है। युवाओं की जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षण, आर्थिक-सामाजिक बाधाओं की पहचान और प्रशिक्षण के बाद रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी जरूरी है।

ग्लोबल स्किल पार्क से प्लेसमेंट की उम्मीद

राज्य सरकार स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन के तहत उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा खेल एवं युवा कल्याण विभागों के समन्वय से काम कर रही है। इसका उद्देश्य युवाओं को शिक्षा, रोजगार और शारीरिक-मानसिक विकास के अवसरों से जोडऩा है। भोपाल का ग्लोबल स्किल पार्क इस दिशा में एक प्रमुख पहल है। यहां उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षुओं को प्लेसमेंट से जोडऩे का प्रयास किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यहां प्रशिक्षुओं को सालाना तीन से १२ लाख रुपये तक के पैकेज मिल रहे हैं। आईटीआई, इंजीनियरिंग और ग्रामीण पृष्ठभूमि के युवा भी प्रशिक्षण ले रहे हैं। ग्लोबल स्किल पार्क की सीईओ अदिति गर्ग के मुताबिक, युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के लिए कई स्तरों पर काम किया जा रहा है। नई पीढ़ी को नए कौशल सिखाकर रोजगार के लिए तैयार करने पर जोर है। उनके अनुसार, ग्लोबल स्किल पार्क ने ९८ प्रतिशत प्लेसमेंट दर हासिल की है।

राष्ट्रीय तुलना में १६वें स्थान पर प्रदेश

एनएसओ की रिपोर्ट में शामिल २९ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में मध्यप्रदेश १६वें स्थान पर है। बिहार में १५ से २९ वर्ष के युवाओं में एनईईटी श्रेणी का अनुपात सबसे अधिक ३२.१ प्रतिशत है। पश्चिम बंगाल में यह २९.९ प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में २९.१ प्रतिशत है। सिक्किम में यह सबसे कम ८.४ प्रतिशत दर्ज किया गया। बिहार और सिक्किम के बीच २३.७ प्रतिशत अंकों का अंतर है। एनईईटी यानी नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग श्रेणी में १५ से २९ वर्ष के वे युवा शामिल होते हैं, जो न शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, न रोजगार में हैं और न ही किसी प्रशिक्षण में हिस्सा ले रहे हैं। यह सामान्य बेरोजगारी दर से अलग पैमाना है। रिपोर्ट वर्ष २०२५ के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पर आधारित है। भोपाल के आंकड़े एक अहम सवाल छोड़ते हैं कि जब राजधानी में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार से जोडऩे की पहल मौजूद है, तो युवाओं का इतना बड़ा हिस्सा इन अवसरों से दूर क्यों है? चुनौती अब योजनाओं की संख्या बढ़ाने से आगे बढक़र उन युवाओं तक पहुंचने की है, जो शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार के मौजूदा तंत्र से बाहर हैं।

पति की दीर्घायु की कामना का पर्व करवा चौथ आज

सजना के लिए सजने बाजारों में जमकर खरीदारी

जबलपुर, (एजेंसी)। पति की दीर्घायु की कामना के लिए सुहागिन महिलाएं आज करवा चौथ का निर्जला व्रत रखेंगी और शाम को चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का समापन करेंगी। करवा चौथ का व्रत पिछले कुछ वर्षो से बड़े उत्साह और आधुनिकता के साथ इस दिन महिलाएं और युवतियां पूरे साजो श्रंगार के साथ अपने सजना के लिए सजती है। करवा चौथ की पूर्व संध्या पर बाजारों में काफी चहल पहल रही। नई नई साड़ियों के साथ लहंगा चूड़ी बिंदी आदि सौंदर्य प्रसाधन की जमकर खरीदारी हुई। दूसरी ओर पूजन समाग्री के लिए करवा और धान की बाली आदि की जमकर बिक्री हुई। ज्योतिष शास्त्रीयों के मुताबिक करवा चौथ के दिन गुरुवार को चंद्रमा रात ०८.१५ बजे नजर आएगा। यह पर्व पति की दीर्घायु एवं परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए रखा जाता है।

पंडित पीएल गौतमाचार्य के मुताबिक यह व्रत दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव को दूर करने के साथ चंद्रमा के प्रभाव से मन को शीतलता भी प्रदान करता है। करवा चौथ के व्रत में मिट्टी से बने करवा में पूजन सामग्री रखकर भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान भोले शंकर जी के पूजन का विधान है। करवा चौथ कार्तिक मास की चतुर्थी को होता है। इस दिन करवे की पूजा की जाती है। यह पर्व पार्वती देवी की आराधना का पर्व है। माता पार्वती जी को स्त्रियों के अक्षत सुहाग का प्रतीक माना गया है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक माता सीता ने भी मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम को पति के रूप में प्राप्त करने के बाद माता पार्वती की आराधना करते हुए सर्वप्रथम कार्तिक चतुर्थी का व्रत किया था।

पूजन विधि

करवा चौथ के दिन व्रत रखें और एक पटे पर जल से भरा लोटा रखें। मिट्टी के एक करवे में गेहूं और ढक्कन में चांवल, गुड़ आदि से गणपति की पूजा करें। रोली से करवे पर स्वास्तिक बनाएं और १३ बिंदियां रखें। स्वयं भी बिंदी लगाएं और गेहूं के १३ दाने दांए हाथ में लेकर कथा सुने। कथा सुनने के बाद अपनी सासूजी के चरण स्पर्श करें और करवा उन्हें दे दे।

महिला पटवारी से दुष्कर्म का प्रयास, मकान मालिक पर आरोप

बटियागढ़, (एजेंसी)। महिला पटवारी के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। पीड़िता आरोपी मकान मालिक के घर किराए से रहती है। घटना सोमवार रात की है, जब महिला का पति अपनी बेटी को लेकर दूसरे शहर गया हुआ था। घर में महिला को अकेला पाकर मकान मालिक ने उसके साथ कथित तौर पर गलत हरकत की।

पीड़िता ने विरोध करते हुए आरोपी को धक्का दिया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। इसके बाद उसने परिजनों को घटना की जानकारी दी। मंगलवार को महिला अपने पति के साथ थाने पहुंची और पुलिस से शिकायत की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पीएम आवासके तहत बने किसानके मकानको गिरानेके नोटिसपर हाईकोर्ट की रोक

मैहर के हरनामपुर गांव का मामला, पड़ोसी की शिकायत पर प्रशासन ने जारी किया था नोटिस

जबलपुर, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मैहर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने एक किसान के मकान को गिराने के प्रशासनिक नोटिस पर रोक लगा दी है। अदालत के अंतरिम आदेश से किसान को फिलहाल राहत मिली है। जस्टिस मनिंदर एस. भट्टी की एकलपीठ ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। प्रकरण की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी।

पड़ोसी की शिकायत पर जारी हुआ था नोटिस

मामला मैहर जिले के ग्राम हरनामपुर का है। यहां रहने वाले किसान शनि दयाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मकान गिराने के लिए जारी नोटिस को चुनौती दी थी। याचिका के अनुसार, वर्ष २०२१-२२ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण के लिए उन्हें भूमि आवंटित की गई थी। यह भूखंड खसरा नंबर २७ पर स्थित है।

याचिका में बताया गया कि पड़ोस में रहने वाली गीता पांडेय ने शिकायत की थी कि मकान निर्माण के कारण उनके आने-जाने के रास्ते पर अतिक्रमण हुआ है। इसी शिकायत के आधार पर प्रशासन ने किसान को मकान गिराने का नोटिस जारी किया।

वास्तविक स्थिति की जांच किए बिना कार्रवाई का आरोप

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने मौके की वास्तविक स्थिति का समुचित परीक्षण किए बिना ही मकान गिराने का नोटिस जारी कर दिया। किसान ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट से राहत की मांग की। प्रारंभिक सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमित मिश्रा ने पक्ष रखा और प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए मकान को ध्वस्त किए जाने से संरक्षण देने की मांग की।

अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद

मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद एकलपीठ ने किसान के मकान को गिराने के संबंध में जारी नोटिस पर रोक लगा दी। इसके चलते फिलहाल प्रस्तावित ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रुकी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद निर्धारित की गई है, जिसमें पक्षकारों की दलीलों और प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़े पहलुओं पर आगे विचार किया जाएगा।

नर्स को होटल में बंधक बनाकर युवक ने किया दुराचार

पीड़िता और आरोपित दोनों यूपी के रहने वाले, बाद में दिया था शादी का झांसा, इंकार करने पर थाने पहुंचा मामला

भोपाल, (एजेंसी)। पुराने शहर की मंगलवारा थाना पुलिस ने यूपी की रहने वाली ३५ वर्षीय नर्स की शिकायत पर उत्तर प्रदेश के ही निवासी आरोपी युवक के खिलाफ होटल में बंधक बनाकर दुष्कर्म किये जाने का प्रकरण दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया की वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, और पुराने भोपाल में परिवार के साथ रहते हुए भोपाल के ही एक निजी नर्सिंग होम में नर्स की नौकरी करती है। उसकी पहचान यूपी के ही रहने वाले आरोपी मोहम्मद असद से हुई थी। महिला का आरोप है कि उसके ता और आरोपी के बीच शादी को लेकर बातचीत चल रही थी। इसी सिलसिले में आरोपी भोपाल आया था। आरोप है कि उसने २९ दिसंबर २०२५ को उसे मिलने के लिये मंगलवारा स्थित एक होटल में बुलाया था। महिला के पहुंचने पर आरोपी ने उससे शादी की बात कही। पीड़िता ने कहा की उसके परिवार वाले सोच समझकर जवाब देगें। यह कहते हुए होटल से निकलने का प्रयास किया लेकिन शादी की बात नहीं मानने पर आरोपी ने उसे बंधक बनाते हुए जबर्दस्ती शारीरिक संबध बना डाले। महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने शादी करने का भरोसा दिया। पीड़ित नर्स का आरोप है, कि इस बीच असद ने जरूरत बताकर उससे कुछ रकम उधार ली थी, लेकिन वापस नहीं की। बीते दिनो उसने उसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया और सभी संबंध खत्म कर लिए। इसके बाद पीड़िता थाने पहुंची, उसकी शिकायत पनर पुलिस ने मालमा दर्ज कर आरोपी की धरपकड़ के प्रयास शुरु कर दिये है।

अब उज्जैन में भी जरूरतमंदों की मदद कर सकेंगे सोनू सूद

उज्जैन में सोनू सूद चेरिटी क्लब का हुआ गठन

उज्जैन, (एजेंसी)। फिल्म अभिनेता एवं समाजसेवी सोनू सूद की संस्था सोनू सूद चैरिटी क्लब की एन्ट्री मध्यप्रदेश के उज्जैन शहर में हुई है। विगत दिनों इंदौर रोड़ स्थित निजी होटल प्लेटेल में आयोजित कार्यक्रम में शहर के समाजसेवियों व गणमान्यजनों की उपस्थिति में सोनू सूद चेरिटी क्लब का गठन किया गया। इसके पूर्व यह क्लब मध्यप्रदेश के देवास, इंदौर सहित अन्य कई शहरों में अपनी सेवा गतिविधियों का आगाज कर चुका है। नवनियुक्त क्लब सदस्य महेश चैहान के अनुसार क्लब का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद लोगों की सहायता करना, समाजसेवा की गतिविधियों को बढ़ावा देना एवं अधिक से अधिक लोगों को सेवा कार्यों से जोड़कर समाज में सकारात्मक बदलाव लाना रहेगा।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उज्जैन क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संतोष मालवीय थे। सोनू सूद चेरिटी क्लब एवं चेरिटी फाउंडेशन की एक्जीक्युटिव डायरेक्टर सुमिता साल्वे के साथ ही इंडिया हेड शुभम विजयवर्गीय, प्राशिका दुआ, भानिता शर्मा, धीरेन्द्रसिंह, विपुल मिरजकर, रूपल पांडे, डिम्पल शर्मा, दीक्षा नागदेवे ने उपस्थितजनों को संबोधित कर सोनू सूद के वीडियो का प्रसारण करने के पश्चात आव्हान किया कि इस दीपावली हम छोटे व्यवसायियों से पटाखे, दीये खरीदकर जरूरतमंदों मे वितरीत करें और वर्षा ऋतु में पौधारोपण, सर्दियों में कंबल वितरण, रक्तदान शिविरों का आयोजन, जरूरतमंदों को भोजन वितरण आदि कार्य वर्ष भर कर समाजसेवा को संगठित रूप से करते हुए पीड़ित मानवता की सेवा करें।

इस क्लब के माध्यम से विभिन्न समाजसेवा के क्षेत्र में सक्रिय महिलाओं को एक मंच पर लगाने का प्रयास किया जायेगा।

क्लब के गठन के अवसर पर हेमंतसिंह राणावत, तरूणसिंह भदौरिया, कल्याणसिंह राजावत, राजेश शर्मा, डॉ.प्रदीप पाण्डेय, सौरभ वर्मा, नितिन वर्मा, दिनेश सोलंकी, नवीन सोनी, अवतारसिंह जुनेजा, आशा जायसवाल, नरेन्द्रसिंह पंवार, तरूण राठौर, राहुल मालवीय आदि उपस्थित रहे। समापन उपरांत क्लब सदस्यों ने प्रभु श्री महाकालेश्वर के दर्शन कर सेवा अभियान को सफल करने की प्रार्थना की।

दो महीने से अटकी आईएएस अफसरों की ट्रेनिंग

ओबीसी क्रीमीलेयर के नियमों में उलझा मामला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अमल पर केंद्र ने मांगी स्थिति स्पष्ट करने की मांग, नई और पुरानी भर्तियों पर असमंजस

भोपाल, (एजेंसी)। ओबीसी आरक्षण में क्रीमीलेयर तय करने के नियमों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने से आईएएस अधिकारियों की ट्रेनिंग दो महीने से अटकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के ११ मार्च २०२६ के फैसले के बाद यह सवाल खड़ा हो गया है कि बदले हुए मानदंड नई भर्तियों पर लागू होंगे या पहले की भर्तियों पर भी इनका असर पड़ेगा। केंद्र सरकार ने इस पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के मुताबिक, सरकार चाहती है कि शीर्ष अदालत बताए कि फैसले को किस तरह लागू किया जाए।

ट्रेनिंग अगस्त के तीसरे सप्ताह से शुरू होनी थी, लेकिन नियमों की व्याख्या को लेकर असमंजस के कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। केंद्र सरकार ने २४ अगस्त २०२६ को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत ने २४ सितंबर को इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो अब तक लंबित है। इस बीच डीओपीटी ने सिविल सेवा परीक्षा के पिछले १४ वर्षों के उम्मीदवारों के आंकड़ों का आकलन कर मामले के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की है।

आय के साथ माता-पिता का पद और सामाजिक स्थिति भी अहम

सुप्रीम कोर्ट ने ११ मार्च को दिए फैसले में स्पष्ट किया था कि ओबीसी क्रीमीलेयर का निर्धारण केवल माता-पिता की आय के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसके लिए माता-पिता या अभिभावकों के पद और सामाजिक स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने कहा था कि सरकारी कर्मचारियों और निजी क्षेत्र या सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों के साथ क्रीमीलेयर निर्धारण में अलग-अलग व्यवहार करना अनुचित भेदभाव हो सकता है। अदालत ने केंद्र सरकार की अपील खारिज करते हुए दिल्ली, मद्रास और केरल हाई कोर्ट के फैसलों को सही माना था।

चयन के बाद भी नियुक्ति से वंचित उम्मीदवारों को राहत

यह मामला उन यूपीएससी उम्मीदवारों से जुड़ा है, जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन उनके माता-पिता की सैलरी को आधार बनाकर उन्हें क्रीमीलेयर श्रेणी में रख दिया गया और आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार के अपनाए गए मानदंड को गलत ठहराया। फैसले के बाद अब मुख्य सवाल इसके प्रभाव और लागू करने की प्रक्रिया को लेकर है। क्या इसका लाभ केवल संबंधित उम्मीदवारों और नई भर्तियों तक सीमित रहेगा या पहले की भर्तियों के मामलों की भी समीक्षा करनी होगी? इसी बिंदु पर केंद्र ने अदालत से स्पष्टीकरण मांगा है।

१४ साल के आंकड़ों से प्रभाव का आकलन

डीओपीटी ने पिछले १४ वर्षों की सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े उम्मीदवारों के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। इसका उद्देश्य फैसले के संभावित प्रभाव और उसके क्रियान्वयन से जुड़े पहलुओं को समझना है। हालांकि, अदालत के स्पष्टीकरण के बिना नई और पुरानी भर्तियों पर इसके प्रभाव को लेकर अंतिम स्थिति स्पष्ट नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आगे की प्रक्रिया निर्भर करेगी। जब तक नियमों के लागू होने की सीमा स्पष्ट नहीं होती, तब तक प्रभावित उम्मीदवारों की नियुक्ति और प्रशिक्षण से जुड़े मामलों में अनिश्चितता बनी रह सकती है।

सरकारी वेबसाइट्स पर हैकर्स की नजर

डेटाबेस और पासवर्ड चोरीका खतरा, एमपी-सर्टने जारी किया हाई अलर्ट

भोपाल, (एजेंसी)। प्रदेश सरकार की साइबर सुरक्षा विंग एमपी-सर्ट ने सरकारी पोर्टल की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर चेतावनी जारी की है। दुनिया की लगभग ७० प्रतिशत वेबसाइट में इस्तेमाल होने वाले पीएचपी सॉफ्टवेयर के मुख्य इंजन में दो गंभीर सुरक्षा खामियां मिली हैं। इन खामियों की वजह से साइबर हमलावर बिना यूजर आईडी और पासवर्ड के अनधिकृत अनुरोध भेजकर सर्वर पर पूरा नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। इस खतरे की जद में राज्य के लगभग ३० सरकारी विभागों की वेबसाइट आ गई हैं। एमपी-सर्ट ने सभी प्रभावित विभागों और सेवा प्रदाताओं को तत्काल सुरक्षा पैच अपडेट करने के निर्देश दिए हैं।

सुरक्षा खामियों का बड़ा खतरा

तकनीकी जांच के अनुसार यह सुरक्षा खामी वेबसाइट के मूल इंजन की मेमोरी सुरक्षा से जुड़ी है। इसका गलत फायदा उठाकर हैकर्स डेटाबेस के पासवर्ड, गोपनीय चाबियां और उपयोगकर्ताओं के सक्रिय सत्र टोकन आसानी से चुरा सकते हैं। वर्डप्रेस, ड्रुपल और जूमला जैसे लोकप्रिय मंचों पर बनी वेबसाइट भी इस खतरे से प्रभावित हो सकती हैं। यह सुरक्षा चूक पीएचपी के पुराने संस्करणों में लगभग १० वर्षों से मौजूद थी। हाल ही में सुरक्षा शोधकर्ताओं ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल की मदद से संभावित हमलों का प्रदर्शन करके इस जोखिम को उजागर किया है।

विभागों को आवश्यक निर्देश

एमपी-सर्ट ने राज्य के सभी विभागों को अपने सर्वर पर पीएचपी के वर्तमान संस्करण की जांच करने की सलाह दी है। इसके साथ ही आधिकारिक सुरक्षा पैच को तुरंत स्थापित करने और प्रक्रिया पूरी होने के बाद बैकएंड सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए कहा गया है। अधिकारियों का कहना है कि पीएचपी किसी भी वेबसाइट को संचालित करने वाला मुख्य प्रोग्रामिंग इंजन होता है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरने और परिणाम देखने जैसे कार्य पूरे होते हैं। चेतावनी जारी होने से पहले ही सुरक्षा टीमों ने कुछ खामियों को पकड़ लिया था।

छह कारों में स्टंटबाजी, खिड़कियों से लटके युवक, सड़क पर मचाते रहे हुड़दंग

घमापुरसे भानतलैया मार्गपर आधी रात तक दौड़ता रहा कारोंका काफिला

जबलपुर, (एजेंसी)। छह कारें, कर्कश हॉर्न, चारों इंडिकेटर चालू और खिड़कियों से बाहर लटकते युवक। किसी कार के पैदान पर खड़े होकर तो कोई गाड़ी से बाहर निकलकर शोर-शराबा करता नजर आया। फिल्मों में दिखने वाला यह नजारा मंगलवार की रात घमापुर से भानतलैया जाने वाले मार्ग पर हकीकत में दिखाई दिया। तेज रफ्तार से दौड़ती कारों के इस काफिले को देखकर सड़क पर चल रहे लोग सहमकर किनारे होते रहे, लेकिन युवाओं की स्टंटबाजी पर रोक लगाने वाला कोई नजर नहीं आया।

रात करीब १२ बजे हाईकोर्ट चौराहे की ओर से छह कारों का काफिला तेज रफ्तार से घमापुर की तरफ बढ़ा। कारों में सवार युवक शोर मचाते हुए मस्ती में झूम रहे थे। कुछ युवक खिड़कियों से बाहर लटक रहे थे, तो कुछ लग्जरी कारों के पैदान पर खड़े दिखाई दिए। सड़क पर सामान्य यातायात के बीच इस तरह की हरकतों से हादसे का खतरा बना रहा। कारों के बीच-बीच में अचानक ब्रेक लगाने से सड़क पर चल रहे लोग भी चौंकते रहे। काफिले की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोग अपने वाहनों के साथ सड़क किनारे रुकने को मजबूर हो गए। कारों का काफिला घमापुर चौराहे तक पहुंच गया, लेकिन युवकों का हुड़दंग जारी रहा।

भोपाल रेलवे स्टेशन के बाहर से सात क्विंटल एनालाग पनीर जब्त

ट्रेन के रास्ते मुरैना से लाया गया

भोपाल, (एजेंसी)। दीपावली त्यौहार से पहले खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार रात २ बजे भोपाल में बड़ी कार्रवाई करते हुए भोपाल रेलवे स्टेशन के बाहर से ७ क्विंटल एनालॉग पनीर जब्त किया है। बताया गया है बड़ी मात्रा में यह पनीर ट्रेन के जरिए मुरैना से यहां लाया गया था। जप्त किये गये ७०० किलो से अधिक एनालॉग पनीर की कीमत करीब ढाई लाख लाख रुपए है। विभागीय अधिकारियों ने पनीर से सबंधत दस्तावेजो के आधार पर प्रकरण दर्ज कर आगे की छानबीन शुरु कर दी है। मप्र में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध के बाद यह पहली कार्रवाई है। पनीर जप्त करने के बाद टीम अब पनीर सप्लाई चैन के तार खंगाल रही है। जॉच के आधार पर संबंधित के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है की करीब तीन महीने पहले सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश में भी एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाया था। एनालॉग पनीर की बिक्री को लेकर तीन महीने पहले राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी नाराजगी जताई थी। आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों को पत्र लिखने का फैसला किया था। इसी बीच सरकार ने पूरे प्रदेश में इस तरह के पनीर पर रोक लगा दी थी।

आदिवासी सीटों पर कांग्रेस का 'प्लस-६०' प्लान

२०२८ से पहले हर विधानसभा का बनेगा अलग सियासी डाटा आरक्षित ४७ सीटों से आगे गैर-आरक्षित क्षेत्रों पर भी नजर

भोपाल, (एजेंसी)। मध्यप्रदेश में २०२८ के विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत कांग्रेस ने आदिवासी राजनीति का दायरा बढ़ाने की रणनीति बनाई है। पार्टी की नजर अब अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित ४७ विधानसभा सीटों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन ६० अतिरिक्त सीटों पर भी है, जहां आदिवासी आबादी चुनावी समीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कांग्रेस इस रणनीति को 'प्लस-६०' प्लान के तौर पर आगे बढ़ा रही है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को इस पहल के समन्वय की जिम्मेदारी दी ग